



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/17/2018

दिनांक : 20.02.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बैंकों के निजीकरण की एसोचैम की माँग

हाल में पंजाब नेशनल बैंक में हुई ₹0 11400 करोड़ की धोखाधड़ी को देखते हुए एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिया है। एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने इसकी निंदा करते हुए 18.02.2018 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की है, जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, एआईबीईए
द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति

18.2.2018

- हम बैंकों के निजीकरण के लिए एसोचैम की माँग की निंदा करते हैं
- उन्हें अपने सदस्यों को बैंक ऋण चुकाने की सलाह देनी चाहिए
- एसोचैम को बैंकों से धोखाधड़ी करने के लिए निरव मोदी की निंदा करनी चाहिए

यह बहुत अजीब और रोचक है कि उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों के मुखपत्र, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स, ने पीएनबी में हालिया धोखाधड़ी के मद्देनजर बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिया है। वे हमारे देश में निजी बैंकों के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड को आसानी से भूल गए हैं।

1948 तथा 1968 के मध्य विफल एवं समामेलित होने वाले, कार्य करने के लिए समाप्त/अपनी देनदारियों और परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने वाले, परिसमापन में जाने वाले निजी बैंकों की संख्या

1948	45
1949	55
1950	45
1951	60
1952	31
1953	31
1954	27
1955	29

1956	28
1957	30
1958	28
1959	38
1960	26
1961	47
1962	33
1963	20
1964	82
1965	42
1966	17
1967	15
1968	7
20 वर्षों में	736 निजी बैंक

निजी बैंक जो कृप्रबंधन के कारण सार्वजनिक हित में अधिस्थगन के तहत रखे गए और 1969 से अस्तित्व से बाहर हो गए

1969	1. बैंक ऑफ बिहार
1970	2. नेशनल बैंक ऑफ लाहौर
1971	3. ईस्टर्न बैंक
1974	4. कृष्णराव बल्देव बैंक
1976	5. बेलगाम बैंक
1985	6. लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक
1986	7. मिराज स्टेट बैंक
1986	8. हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक
1990	9. ट्रेडर्स बैंक लि०
1990	10. बैंक ऑफ तमिलनाड
1990	11. बैंक ऑफ थंजावुर
1991	12. परुर सेण्ट्रल बैंक
1991	13. पूर्वांचल बैंक
1993	14. बैंक ऑफ कराड लि०
1995	15. काशीनाथ सेठ बैंक
1997	16. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि०
1997	17. बरी दोआब बैंक लि०
1999	18. बरेली बैंक लि०
1999	19. 20 संचुरी फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि०
1999	20. ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट
1999	21. सिक्किम बैंक लि०
2000	22. टाईम्स बैंक लि०

2001	23. बैंक ऑफ मदुरा
2002	24. बनारस स्टेट बैंक लि०
2003	25. नेदुंगदी बैंक लि०
2004	26. साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक
2004	27. बैंक मस्कट एसएओजी
2004	28. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि०
2006	29. बैंक ऑफ पंजाब
2006	30. गणेश बैंक ऑफ कुरुंडवाड
2006	31. यूएफजे बैंक लि०
2007	32. यूनाईटेड वेस्टर्न बैंक
2007	33. लॉर्ड कृष्णा बैंक
2007	34. संगली बैंक
2007	35. भारत ओवरसीज बैंक
2008	36. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब

यदि निजी बैंक वास्तव में कुशल हैं, तो ये बैंक क्यों बंद हो गए और अन्य के साथ विलय कर दिये गए। इनमें से ज्यादातर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के साथ विलय कर दिए गए। कई निजी बैंकों की विफलता के जहर को निगलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नीलकंठ महादेव बन गए और यह हास्यास्पद है कि एसोचैम अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए कह रहा है। हम उनके लालच को समझते हैं लेकिन वे यह दावा नहीं कर सकते कि निजी बैंक अधिक कुशल हैं।

दूसरे, बैंकों में चिन्ताजनक रूप से बढ़ते हुए खराब ऋणों को लें। कौन अपराधी हैं और कौन चूककर्ता हैं ? क्या वे सभी निजी कंपनियों, उद्योगपति और कॉर्पोरेट घराने नहीं हैं ? एनपीए के 12 मामलों को दिवालियापन और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए एनसीएलटी के पास भेजा गया है जिसमें रू० 253,000 करोड़ शामिल हैं। वे कौन हैं ? क्या वे सभी शीर्ष निजी कॉर्पोरेट उधारकर्ता नहीं हैं। उन्होंने ऋणों को क्यों नहीं चुकाया ? क्या यह उनकी दक्षता है ? क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए और इन लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए ?

पीएनबी धोखाधड़ी में, कोई संदेह नहीं कि उन अधिकारियों के हिस्से पर क्षमा न किए जाने योग्य पाप है जो निरव मोदी की सहायता के लिए कार्यशैली से बाहर चले गए। लेकिन किसने उन्हें प्रलोभन दिया और उनको प्रभावित किया ? क्या यह निजी कॉर्पोरेट दैत्य निरव मोदी नहीं है ? हमारे देश में किसी प्रमुख धोखाधड़ी को लें। इसमें निजी कॉर्पोरेटों का हाथ दिखाई देगा।

उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋणों का बड़ा भाग निजी कॉर्पोरेट घरानों के लिए है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुशल नहीं हैं, तो वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से इन ऋणों को क्यों प्राप्त करते हैं और निजी बैंकों से ऐसे ऋणों को क्यों नहीं लेते हैं ?

शैतान को पवित्र शास्त्रों का उद्धरण नहीं देना चाहिए। हम एसोचैम को निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के ऋणों को चुकाने की सलाह देने और निमो की पीएनबी में उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए निंदा करने के लिए सलाह देते हैं।